राष्ट्रीय सागर | झारखण्ड | गुरुवार | रांची, 06 नवंबर 2014

कागज के पेड़ों पर पलते रेशम के कीड़े

जसिन्ता केरकेट्टा

पहाड़ियाओं के लिए करोड़ों रूपये का आवंटन होता है। पर इसका हाल यह है कि इससे सिर्फ सरकारी, गैर-सरकारी संगठन ही अपनी आजीविका पुख्ता कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। इसके अतिरिक्त लोगों की जमीनों पर गैर जरूरी भवन- केंद्र बनाकर उनकी आजीविका पर मंडराते संकटों को और बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। आदिम जनजाति पहाड़ियाओं के आर्थिक उन्नयन व उनकी आजीविका की समस्या को दूर करने के लिए जिले में रेशम-पालन योजना चलायी जा रही है, जिसका हश्र यह है कि रेशम के कीड़े कागज के पेड़ों पर ही पल रहे हैं। यह जान कर बड़ा आश्चर्य होगा कि साहेबगंज जिले में आदिम पहाड़िया जनजाति के आर्थिक उन्नयन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कागज के पेड़ों पर हो रहा है। पर, यह हकीकत है। आदिम जनजातियों के समाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नयन के लिए सरकार के तीन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। पहाड़ियाओं के लिए विशेष विभाग की स्थापना की गई है। इसके विशिष्ट पहाड़िया पदाधिकारी हैं। जिला कल्याण विभाग और समेकित जनजातीय विकास अभिकरण द्वारा भी उनके विकास का काम होता हैं। समेकित विकास अभिकरण के तहत पहाड़ियाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। यह पहाड़ियाओं के लिए बिरसा आवास तैयार करने के साथ आजीविका के साधनों को बढ़ाने के लिए काम भी करता है। इसके तहत जल संरक्षण, सिंचाई की व्यवस्था, प्री व पोस्ट कोकून पालने, रेशम तैयार करने और उसके मार्केटिंग का किया जाता है। विभाग यह काम एनजीओ के माध्यम से करता है।

आम पहाड़िया आदिवासी पहाड़ों पर रहते हैं और बांस, लकड़ी बेचने व मकई, बरबट्टी उगाने का काम करते हैं। इससे ही उनकी आजीविका चलती है। कुछ पहाड़ियाओं की जमीनें तराई क्षेत्रों में है। वे धान की खेती करते हैं। भोजन के दृष्टिकोण से पहाड़ियाओं के लिए साल के तीन महीने दुष्कर होते हैं। सितंबर, अक्तूबर और नंवबर में खेतों में फसलें लगी होती है इसलिए वे सिर्फ बांस और लकड़ी बेचने पर निर्भर रहते हैं। घर में खाने को अनाज नहीं होता, क्योंकि प्रखंड से मिलने वाला चावल भी वे एक बार एक साथ ही उठाते हैं। प्रखंड या डीलर से उन्हें पूरा चावल भी नहीं मिलता। अक्सर 35 की जगह 30 किग्रा. चावल ही दिया जाता है।

2005 से आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए पहाड़ियाओं की जमीन पर उनके ही सहयोग से रेशम-पालन की योजना शुरू की गयी। इसके तहत किसी एनजीओ को पूरा काम सौंप दिया जाता है। एनजीओ को ही प्री कोकून व पोस्ट कोकून दोनो तैयार कर उसकी मार्केटिंग कर प्राप्त राशि पहाड़ियाओं को देनी है।

विभाग के निदेशक शिवजी चौपाल के अनुसार वर्ष 2005-08 में रेशम-पालन के लिए फेज-वन के तहत 578.20 करोड़ रुपये आवंटित हुई, जिसमें विभाग को 468.86 करोड़ ही मिले। इसमें भी 63.27 लाख रुपये का कोई उपयोग नहीं हो सका। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि प्री कोकून के बाद पोस्ट कोकून के लिए कम्यूनिटी फेसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाना है। कोकून से तसर निकालने के लिए मशीनें भी चाहिए। मशीनें खरीदने और काम करने के लिए अब तक किसी एनजीओ का चयन नहीं हुआ है। इसलिए काम रूका हुआ है।

वर्ष 2007-10 में पोस्ट कोकून कार्य के लिए दो करोड़ 18 लाख 64 हजार रुपये खर्च किये गये और 19 कम्यूनिटी फेसिलिटी सेंटर बनाए गए। इन भवनों में क्या काम हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उनके अनुसार वर्ष 2011-12 व वर्ष 13-14 तक मंडरो प्रखंड में 21 लाख रूपये में 50 एकड़ और 44 लाख रूपये में 37 एकड़ जमीन पर प्री कोकून का काम शुरू किया गया है। योजना के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि आदिम पहाड़िया जनजाति के जीवन स्तर में इससे बड़ा बदलाव आएगा। उनकी आजीविका से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। बरहेट प्रखंड के अरगौड़ी गांव में दौरा करने पर यहां पोस्ट कोकून के लिए कम्यूनिटी फेसिलिटी सेंटर दिखा। इसके ठीक पीछे की जमीन को रेशम के कीड़े पालने के लिए घेरा गया था। गांव के लोगों ने इस सेंटर निर्माण के लिए अपनी जमीनें दी थी। गांव के प्रधान सूरजा पहाड़िया ने 2 कट्ठा जमीन दिया है। वहीं, गांव के देवा पहाड़िया व देवा मास्टर ने भी अपनी जमीनें दी हैं। उनकी जमीनों पर कम्युनिटी फेसिलिटी सेंटर खड़ा हो गया, लेकिन न प्री कोकून तैयार करने के लिए पेड़ लगे, न पेड़ों पर कोकून लगे और न ही सेंटर में पोस्ट कोकून से तसर ही निकला। यह सेंटर साल 2007-09 के लिए खोला गया था लेकिन यहां कोई काम नहीं हुआ। सूरजा पहाड़िया कहते हैं कि उनकी जमीन पर यह सेंटर बेकार का खड़ा है। गांव के लोग अब वहां गाय-बैल बांधते हैं। लोगों को इस सेंटर की जरूरत नहीं है। गांव के लोग बताते हैं रेशम के कीड़े पालने के लिए न तो पौधे लगाए गए न ही रेशम कीड़ों का पालन ही कभी गांव में शुरू हुआ। दूसरी ओर कागजी पेड़ों पर रेशम के कीड़े खूब पल रहे हैं और उन पर पहाड़ियाओं के लिए आवंटित राशि खर्च हो रही है। मार्केटिंग के बाद पहाड़ियाओं को कितनी राशि दी गई, इसके आंकड़े सरकारी पत्रों से गायब हैं। यही हाल अन्य पहाड़ों पर स्थित गांवों में भी देखने को मिला। कई गांवों के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनके लिए रेशम-पालन की योजनाएं चल रही है। दूसरी ओर मंडरो प्रखंड में कोकून से रेषम के धागे निकालने का प्रषिक्षण लेने के बाद भी महिलाएं बेरोजगार बैठी हैं क्योंकि इस क्षेत्र में आधे काम के बाद राषि की निकासी व वितरण नहीं हो पाने के कारण काम रूका हुआ है। जिसके कारण महिलाओं व ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं के प्रति मायूसी छाई हुई है।

बिरसा आवास की राशि हुई लैप्स : पहाड़ियाओं के लिए सरकार पहाड़ों पर बिरसा आवास का निर्माण कराती है। साल 2001-02 से 2013-14 तक 1317 बिरसा आवासों के निर्माण की योजना थी। इसमें 1170 योजनाएं ली गई। पर मात्र 761 ही पूर्ण हुई। 230 योजनाओं की दो करोड़ तीस लाख रुपये की राशि लैप्स कर गयी। कागजों पर पूर्ण दिखाये गये योजनाओं में भी पहाड़ियाओं ने अपने पैसे लगाकर आधे-अधूरे भवनों का निर्माण पूरा किया है। हां, पहाड़ियाओं के लिए आवंटित राशि से सरकारी, गैर-सरकारी संस्थानों की आजीविका खूब फल फूल रही है।

सीएसडीएस द्वारा प्रदत्त इनक्लूसिव मीडिया यूएनडीपी फेलोशिप के तहत रिपोर्टिंग